



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2018/माघ 4, 1939

No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018/MAGHA 4, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2018

विषय - चीन जनवादी गणराज्य से "मेटा-फिनाइलीन डायमीन-4-सल्फोनिक एसिड (एमपीडीएसए)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

फा सं. 6/35/2017-डीजीएडी.— मै. चामुडा इंडस्ट्रीज, मातृशक्ति इंडस्ट्रीज एवं वाराही इंटरमीडिएट्स (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित मेटा-फिनाइलीन डायमीन-4-सल्फोनिक एसिड (एमपीडीएसए)(जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद मेटा-फिनाइलीन डायमीन-4-सल्फोनिक एसिड है (जिसे आगे "एमपीडीएसए" या "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है)। एमपीडीएसए एक सलेटी सफेद क्रिस्टल गंधरहित पाउडर/केक होता है। इसमें तीन किस्में जैसे एमपीडीएसए (फ्री एसिड), एमपीडीएसए (सोडियम साल्ट) और एमपीडीएसए (एसिटाइल) होती हैं। यह एक रसायन के रूप में कार्य करता है और इसका डाइस्टफ उत्पादों के लिए मध्यवर्ती वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

3. विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के उपशीर्ष 2922 29 26 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद का वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

4. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु समान वस्तु है। संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबंधित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह याचिका मै. चामुडा इंडस्ट्रीज, मातृशक्ति इंडस्ट्रीज एंड वाराही इंटरमीडिएट्स द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर की गई है। प्रस्तावित पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 56.75 प्रतिशत है। आवेदकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने वाली सात और कंपनियां हैं- बेंजो प्राइवेट्स (इंडिया) प्रा. लि., ब्लू आर्क इंडस्ट्रीज, अनमोल डाइस्टफ प्रा. लि., प्रतीक डाइज एंड इंटरमिडियरीज, राकेश कैमिकल इंडस्ट्रीज, उमिया कैम इंटरमिडिएट्स और क्लासिक इंडस्ट्रीज।

6. आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने पूरी क्षति अवधि और प्रस्तावित जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। चूंकि आवेदकों का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में "प्रमुख हिस्सा" बनता है इसलिए आवेदक नियमावली के भीतर घरेलू उद्योग की योग्यता रखते हैं और घरेलू उद्योग हैं।

शामिल देश

7. वर्तमान जाँच चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

8. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाए।

9. तथापि, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट कर सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

क. कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

10. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की लागत और कीमतों के बारे में सूचना/साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में, संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत के आधार पर, कच्ची सामग्री और सुविधाओं के लिए घरेलू उद्योग के खपत मानकों पर विचार करते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित करते हुए लगाया गया है। प्राधिकारी ने संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य प्रथम दृष्टया परिकलित मूल्य के आधार पर माना गया है जैसा कि इस जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदकों ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (जिसे आगे डीजीसीआईएस भी कहा गया है) से प्राप्त आकड़ों के आधार पर कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की है और समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे संबद्ध देश के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदकों द्वारा क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है। आवेदकों ने दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति विभिन्न मापदंडों जैसे पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा, संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों में गिरावट, भारी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, भारी वित्तीय घाटे, निवेश पर आय, नकद प्रवाह के कारण हुई काफी बढ़ गई है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ जैसे मापदंडों के संबंध में विकृति आई है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेशों पर ऋणात्मक आय हो रही है।

14. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि चीन जन. गण. से आयातों में उछाल आया है। अतः आवेदक ने दावा किया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आयातों में भारी वृद्धि, आयात कीमत में गिरावट, भारी कीमत कटौती, कीमत पर बिक्री संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के आधार के रूप में दावा किया है।

पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

15. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और

प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच अवधि

16. याचिकाकर्ताओं ने 2016-17 का प्रस्ताव इस जाँच के लिए जाँच अवधि के रूप में किया है। तथापि, अधिक हाल के आकड़ों के लिए प्राधिकारी ने 15 महीने (अप्रैल 2016 - जून, 2017) की अवधि को जाँच अवधि के रूप में रखने का निर्णय लिया है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016 और जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

19. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध) करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो दो अलग-अलग सेट प्रस्तुत करने अपेक्षित होंगे।

22. 'गोपनीय' और 'अगोपनीय' अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' और 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों अंशों की साफ्ट कॉपियों के साथ साथ प्रत्येक सेट की दो-दो (2-2) प्रतियों के साथ हार्ड प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना होनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसका प्रदाता उसके गोपनीय होने का दावा करता है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई या गोपनीयता के दावे वाली सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. किसी सार्वजनिक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

27. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2018

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Meta-Phenylene Diamene-4-Sulphonic Acid (MPDSA)” from People’s Republic of China

F. No. 6/35/2017-DGAD.—M/s. Chamunda Industries, Matrushakti Industries and Varahi Intermediates (hereinafter referred to as the ‘applicants’) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of Meta-Phenylene Diamene-4-Sulphonic Acid (MPDSA) (hereinafter referred to

as the “subject goods”) originating in or exported from People’s Republic of China (hereinafter referred to the “subject country”).

Product under Consideration

2. The product under consideration is Meta Phenylene Diamine 4 Sulphonic Acid (hereinafter also referred to as “MPDSA” or the “subject goods” or the “product under consideration”). MPDSA is a greyish white crystal odourless powder/cake. It has three variants such as MPDSA (Free Acid), MPDSA (Sodium Salt) & MPDSA (Acetyl). It functions as a chemical, and also used as intermediate for dyestuff products.

3. The product under consideration is generally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under sub heading 2922 29 26. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances

Like Article

4. The applicants have submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the applicants. The product concerned produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country

Domestic Industry and Standing

5. The Petition has been filed by M/s Chamunda Industries, Matrushakti Industries and Varahi Intermediates, as domestic industry of the product under consideration. The applicants’ share in Indian production of product under consideration is 56.75% during the proposed POI. Apart from the applicants, there are seven more companies manufacturing the subject goods in India - Benzo Products (India) Pvt. Ltd., Blue Ark Industries, Anmol Dyestuff Pvt. Ltd., Pratik Dyes & Intermediaries, Rakesh Chemical Industries, Umiya Chem Intermediates and Classic Industries.

6. The applicants have certified that they have neither imported the subject goods during the entire injury period and proposed period of investigation nor are related to any of the exporters or importers of the subject goods. Since the production of the applicants accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India, the applicants satisfy the standing and constitute Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Countries Involved

7. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from People’s Republic of China.

Normal Value

8. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and its normal value be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

9. However, while submitting the questionnaire response producers/ exporters may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and (sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
- b. Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
- c. The producers/exporters are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

10. The applicants have submitted that efforts were made to get information/evidence about cost and prices of subject goods in the domestic market of the subject country. In the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject country, the Normal value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production, considering consumption norms of the domestic industry for raw material and utilities, duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject country on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

11. The applicants have determined the ex-factory export price on the basis of data procured from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (hereinafter also referred to as DGCIS) and has made adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

13. The applicants have furnished information on various parameters relating to injury. The applicants have claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports exemplified by various parameters such as significant subject imports over the injury period in absolute terms as also relative to the production and consumption in India, decline in import prices of the subject goods, significant price undercutting, price depression, financial losses, return on investments, cash flow. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments.

14. The applicants have also claimed that imports have spurred from China PR. Applicant has therefore claimed that the imports are threatening material injury to the domestic industry. Applicant has submitted

that there is significant increase in imports, decline in import price, significant price undercutting, price depression as grounds for claiming threat of material injury to the domestic industry from subject imports.

Initiation of the Anti-Dumping Investigation

15. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; material injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation and accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating from the subject country and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

16. The petitioners have proposed 2016-17 as the period of investigation for this investigation. However, in order to have more recent data, the Authority has decided the period of 15 months (April, 2017 to June, 2017) as the period of investigation. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2013 – March 2014, April 2014 – March 2015, April 2015 – March 2016 and the POI.

Submission of Information

17. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001

18.

ny other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties

Time Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

21. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.

22. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

23. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

27. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

28. In terms of Rule 6 (7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. \

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority